आईआईआईडीईएम ने भूटान के मीडिया कर्मियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया

भूटान के चुनाव आयोग के विशेष आग्रह पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में भूटान के मीडिया कर्मियों के लिए 9 जलाई, 2018 से 13 जुलाई, 2018 के बीच 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें भूटान के चुनाव प्रबंधन निकाय के अधिकारी, संवाददाता एवं अन्य मीडिया कर्मी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चुनावों में मीडिया के साथ पारस्परिक संवाद स्थापित करना है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे तानेबाने के साथ जुड़ी है जहां किसी एक जगह की घटना दूसरी जगह को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक परिचर्चाओं एवं सत्रों का आयोजन होगा।

उप-चुनाव आयुक्त श्री सुदीप जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बताया कि चुनावों में मीडिया पर यह अपने प्रकार का ऐसा पहला कोर्स है, जिसका आयोजन आईआईआईडीईएम द्वारा किया जा रहा है।

महानिदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रासंगिक विषयों को रखा जाएगा और उन्होंने सफल परिचर्चा के लिए उम्मीद जताई।

आईआईआईडीईएम के निर्वाचन विशेषज्ञ डॉ. नूर मोहम्मद ने प्रतिभागियों को इस 5 दिवसीय कार्यक्रम की समय सारणी के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में ईएमबी एवं मीडिया संबंध,मतदाता शिक्षा एवं मीडिया विधिक/संस्थागत ढांचा, पेड न्यूज एवं मीडिया कानून, मीडिया के लिए आचार संहिता एवं सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दे, मीडिया से संबंधित उपकरण एवं तकनीक आदि शामिल है।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह के दौरान दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जेई-इन के साथ।

नई रेड बुल बीसी वन ई-बैटल्स में प्रवेश करके रेड बुल बीसी वन लास्ट चांस साइफर में अपना स्थान बनाएं

अब तक, रेड बुल बीसी वन वर्ल्ड फाइनल में निमंत्रण, या एक क्षेत्रीय साइफर जीतकर ही भाग लेना संभव था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फाइनल में हिस्सा लेने का यह नियम बदल गया है। दुनिया भर के ब्रेकर्स को अब नए ई-बैटल्स के माध्यम से क्वालीफाई करके लास्ट चांस साइफर का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।

भाग लेने के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण करें, अपनी ब्रेकिंग का एक वीडियो अपलोड करें- यह 60 सेकंड से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए - और फिर वापस बैठें और प्रतीक्षा करें क्योंकि जज क्वालीफायर के पहले दौर का चयन करते हैं। यह प्रतियोगिता दुनिया भर से सभी बी-बॉयज़ और बी-गर्ल्सफ के लिए खुली है।(22-1)

टेक्वोन डो फेडरेशन ऑफ मार्शल आर्ट में अहमदाबाद की संस्था का अग्रणी स्थान

अहमदाबाद : टेक्वोन डो मार्शल आर्ट में हमारी संस्था महत्व का स्थान रखती है। संस्था लड़के- लड़कियों को टेक्वोन डो का प्रशिक्षण क्वालिफाय कोर्स द्वारा प्रदान करती है। हमारी संस्था के लड़के- लड़कियां स्टेट लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल, एशियन एवं इन्टरनेशनल टेक्वोन डो टूर्नामेंट खेलने जाते है । तथा अनेक मेडल एवं लेवल पर 9 बार चेम्पीयन ट्रोफी हासिल कर चुके है तथा फाइटर अवार्ड भी प्राप्त किया है, यह जानकारी संस्था के टेक्नीकल डायरेक्टर अनिल सोलंकी ने एक पत्रकार गोष्ठी में दी।

इस खेल के टेक्नीकल डायरेक्टर एवं चीफ कोच अनिल सोलंकी ने आगे बताया कि टेक्वोन डो आई.टी.एफ में फोर डिग्री एवं डब्ल्यु.टी.एफ में थर्ड डिग्री ब्लेक बेल्ट धारी है। वे गत 30 सालों से टेक्वोन डो का प्रशिक्षण इन लडके- लड़कियों को दे रहे है। संस्था के पास टेक्वोन डो के 54कोच है। सोलंकी ने एक अपील कर कहा कि समाज को जागरूक कर प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को इस सेल्फ डिफेन्स (टेक्वोन डो)का प्रशिक्षण क्वालिफाइड कोच द्वारा अनिवार्य रुप से दिलाये। जिससे उनके अन्दर एक सेल्फ कोन्फीडेन्स पैदा होगा और वे कहीं भी आने जाने के लिए समर्थ बनेंगे। वे किसी का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।

टेक्वोन डो की भारत में दो संस्था है, आईटीएफ टेक्वोन डो तथा डब्ल्यु.टी.एफ टेक्वोन डो इसी के साथ गुजरात में भी एफिलेटेड आईटीएफ टेक्वोन डो तथा डब्ल्युटीएफ टेक्वोन डो संस्था है। (19-8)

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा ने 'कारोबार में सुगमता' के मामले में शीर्ष रैंकिंग हासिल की

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने आज नई दिल्ली में 'कारोबार में सुगमता' के मामले में राज्यों की अंतिम रैंकिंग जारी की। इस मामले में शीर्ष पायदान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हरियाणा हैं। झारखंड और गुजरात ने इस मामले में क्रमशः चौथी एवं पांचवीं रैंकिंग हासिल की है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीआईपीपी ने विश्व बैंक के सहयोग से 'कारोबार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)' के तहत समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक सुधार सर्वे किया। इस सर्वे का उद्देश्य दक्ष, प्रभावकारी एवं पारदर्शी ढंग से केन्द्र सरकार के विभिन्न नियामकीय कार्यकलापों एवं सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर करना है।

वर्ष 2017 तक सुधार योजना में शामिल कार्य बिन्दुओं की संख्या को 285 से बढ़ाकर 372 कर दिया गया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने श्रम, पर्यावरणीय मंजूरियों, एकल खिड़की प्रणाली, निर्माण परमिट, अनुबंध पर अमल, संपत्ति के पंजीकरण एवं निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में अपने नियम-कायदों एवं प्रणालियों को आसान बनाने के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पंजीकरण एवं मंजूरियों से जुड़ी समय सीमा पर अमल के लिए सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी अधिनियम लागू किया है।

'बीआरएपी 2017' के तहत वर्तमान आकलन एक संयुक्त स्कोर पर आधारित है जिसमें 'सुधार साक्ष्य स्कोर' और 'फीडबैक स्कोर' शामिल हैं। 'सुधार साक्ष्य स्कोर' राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपलोड किए गए साक्ष्यों पर आधारित है, जबकि 'फीडबैक स्कोर' विभिन्न व्यवसायों के लिए मुहैया कराई गई सेवाओं के वास्तविक इस्तेमालकर्ताओं (यूजर) से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है।

डीआईपीपी ने पहली बार फीडबैक लेने की शुरुआत की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू किए गए विभिन्न सुधार वास्तव में जमीनी स्तर पर पहुंच गए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं के 50,000 से भी अधिक यूजर्स में से चयन किए गए वास्तविक इस्तेमालकर्ताओं से आमने-सामने साक्षात्कार लेकर यह फीडबैक संग्रहीत किया गया। 372 सुधारों में से 78 सुधारों को इस सर्वे के लिए चिन्हित किया गया। 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में निजी क्षेत्र के 5000 से भी अधिक इस्तेमालकर्ताओं ने इस सर्वे के दौरान अपने-अपने अनुभव साझा किए जिनमें देश भर के 4300 कारोबारी एवं 800 वास्तुकार, वकील एवं विद्युत ठेकेदार शामिल हैं।

भारत में 'कारोबार में सुगमता' के लिए राज्यों द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों ने अन्य देशों जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी इस मामले में दिलचस्पी काफी बढ़ा दी है जिससे यह साबित होता है कि कारोबारी एवं नियामकीय माहौल बेहतर करने के लिए इस तरह के सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

सेंट्रल 14 जुलाई को पेश करता है रेड हेय्यूट सैटरडे

फ्यूचर ग्रुप का फैशन केंद्र सेंट्रल ग्रुप 14 जुलाई को पेश कर रहा है, 'रेड हेय्यूट सैटरडे'। इस शनिवार को आप अपने नजदीकी सेंट्रल स्टोर में शॉपिंग करें और सेंट्रल इसकी कीमत चुकाएगा। 'रेड हेय्यूट सैटरडे' के अनूठे कॉन्सेप्ट के तहत 'आप खरीदें, पेमेंट हम करेंगे' का फायदा उठाते हुए फैशन प्रेमी जमकर शॉपिंग कर सकते हैं।

'रेड हेय्यूट सैटरडे' के दिन सेंट्रल में सब कुछ 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। साथ ही 3000 रुपए की न्यूनतम खरीदारी पर फ्यूचर पे के सेंट्रल वॉलेट के जरिए आपको 50% कैशबैक भी मिलेगा। शॉपिंग को और मजेदार बनाते हुए ग्राहक 300 रुपए में ऑनलाइन रेड हेय्यूट एंट्री पास खरीद सकते हैं। इस पास से आप स्टोर में खरीदारी तो कर ही सकते हैं, साथ ही आपको एंट्री और बिलिंग में प्राथमिकता भी मिलेगी। फैशन प्रेमी 3000 रुपए की खरीद पर ओला की सवारी पर 200 रुपए की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। 19,000 रुपए की शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को गूगल होम मिनी सिर्फ 499 रुपए में मिलेगा।

ग्राहक 300 रुपए में www.redhautesaturday.com पर रजिस्ट्रेशन करके लंबी लाइनों से छुटकारा पाते हुए पहले बिलिंग का फायदा उठा सकते हैं। रेड हेय्यूट पास वाले 10 ग्राहकों को गूगल होम मिनी जीतने का मौका भी मिलेगा। आप रेड हेय्यूट एंट्री पास ूपदेपकमतण्पद से भी खरीद सकते हैं। (19-10)

बैंक ऑफबड़ौदा ने केबी फाइनेंशियल ग्रुप के साथ एमओयूपर हस्ताक्षर किए

मुंबई, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक- बैंक ऑफबड़ौदा ने केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक (केबीएफजी), कोरिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू इन-को फाइनेंस कॉरिडोर और डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम का गठन करने के लिए दोनों संगठनों के बीच व्यापक व्यापार सहयोग के लिए किया गया है।

9 जुलाई 2018 को भारत-कोरिया बिजनेस फोरम के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु की मौजूदगी में इस एमओयू पर बैंक ऑफबड़ौदा के एमडी और सीईओ श्री पी एस जयकुमार और केबी फाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन डॉ यून जोंग-क्यू ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, बैंक ऑफबड़ौदा के एमडी और सीईओ श्री पी एस जयकुमार ने कहा, ''इस साझेदारी के माध्यम से, बैंक ऑफबड़ौदा और केबी फाइनेंशियल ग्रुप भारत में एक नया डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम बनाने और बैंक ऑफबड़ौदा और केबी वित्तीय समूह के कॉर्पोरेट और खुदरा ग्राहकों को पारस्परिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इन-को कॉरिडोर बनाने पर मिलकर काम करेंगे। हम बैंक ऑफ बड़ौदा के विविध घरेलू नेटवर्क और कोरियाई कारोबारी घरानों के साथ केबी के व्यापार संबंधों के बीच उत्पन्न संभावित सहभागिता का लाभ उठाकर केबी वित्तीय समूह के साथ संयुक्त रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''(1)

अफगान कृषि निर्यातकों और भारतीय खरीदारों का एक दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 13 और 14 जुलाई को होगा

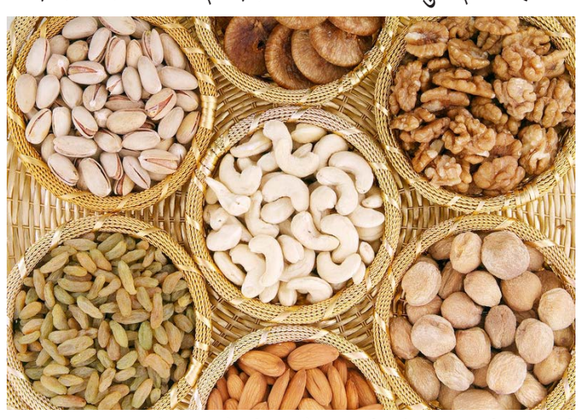

अफगानिस्तान और भारत के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने साथ दक्षिण एशिया में अफगान कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश के लिए 50 से ज्यादा अफगानिस्तान की निर्यात कंपनियां 13 और 14 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन 'मेड इन अफगानिस्तानः नेचर्स बेस्ट' में कारोबारी रिश्ते तलाशने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भारत आ रही हैं।

500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां नई कारोबारी संबंध बनाने और निवेश के अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा के लिए अफगान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी। दो दिवसीय 'मेड इन अफगानिस्तानः नेचर्स बेस्ट' सम्मेलन के दौरान भारतीय खरीदारों के लिए अफगानिस्तान के बेहतरीन फल, बादाम और मसाले प्रदर्शित किये जाएंगे, इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में अफगानिस्तान के कृषि निर्यात को बढावा देना है। दो दिवसीय सम्मेलन भारतीय कारोबारी आयातकों को अफगानिस्तान के निर्यातकों से मिलने और कारोबारी रिश्तों के बढ़ाने का मौका देगा। (1-7)

13 और 14 जुलाई को निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर दो दिन का सेमिनार

जिनेवा स्थित आईआरएफ यानि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की भारतीय शाखा निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर दो दिन का सेमिनार का आयोजन कर रही है। नई दिल्ली में यह सेमिनार 13 और 14 जुलाई 2018 को होगा। आईआरएफ दुनिया में बेहतर और सुरक्षित सड़कों पर काम कर रही अंतरराष्ट्रीय संस्था है।

के के कपिला, चेयरमैन, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने कहा, भारत के बढ़ते और विस्तृत होते इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा शानदार हाईवे सेक्टर का निर्माण है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने और सड़क निर्माण की पूंजी की जरूरत पूरा होने के कारण भारत में हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में निर्माण के दौरान सड़क इस्तेमाल करने वाले और सड़क बनाने वाले दोनों की सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण चिंता का विषय होता है।

श्री कपिला के मुताबिक हाईवे सिस्टम को आधुनिक बनाने के बड़े कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण का लगातार संरक्षण और सुरक्षा सिस्टम को बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। हाईवे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के दौरान इन चुनौतियों का सामना सभी स्तर के पेशेवर अधिकारियों को करना पड़ता है। निर्माण क्षेत्र के पास यातायात का सुरक्षित और लगातार चलना परिवहण अधिकारियों, इंडस्ट्री, पब्लिक, कारोबारियों और कमर्शियल मोटर वाहकों के लिए बड़ी चिंता होता है। प्रासंगिक उप-विषयों के साथ दो दिन का सेमिनार सुरक्षा के लिए डिजाइन के सभी पहलुओं पर रोशनी डालेगा। निर्माण परियोजनाओं के दौरान पर्यावरण संरक्षण, टेक्नोलॉजी, निर्माण के दौरान सुरक्षा, सुरक्षा मुद्दों और जोखिम जैसे विषयों पर भी सेमिनार में बात होगी। सेमिनार का उद्देश्य चुने हुए मुद्दों के कई पहलुओं पर जानकारी का आदान-प्रदान करना है। सुरक्षा के लिए डिजाइन, निर्माण परियोजनाओं के पर्यावरण संरक्षण, टेक्नोलॉजी, निर्माण के दौरान सुरक्षा, सुरक्षा मुद्दों और जोखिम चुने हुए मुद्दे हैं। (1-7)

नए पूर्वोत्तर के विजन से नए भारत का सपना पूरा होगा - गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नए भारत तक जाने का मार्ग विकसित और शांतिपूर्ण नए पूर्वोत्तर से होकर जाता है। शिलांग में आज पूर्वोत्तर परिषद के 67वें पूर्ण अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है 2022 तक नया भारत। नए पूर्वोत्तर के माध्यम से नए भारत का सपना पूरा होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से नया पूर्वोत्तर उभरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि हम गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराते हैं तो क्षेत्र के युवा अपने निवास स्थानों के आसपास ही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इससे स्थानीय युवाओं का देश के सुदूर क्षेत्रों में प्रवास रूक जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि आईटीआई और पोलिटेक्निक संस्थानों को कौशल विकास में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। एनईसी को कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोजगार और आय वृद्धि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों को निजी निवेश के लिए यह बेहतर माहौल प्रस्तुत करना चाहिए ताकि निवेशक सुरक्षित महसूस कर सकें तथा उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

गृह मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास किया जाना चाहिए ताकि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा किया जा सके। हमें निर्यात के लिए 'कम मात्रा उच्च मूल्य' वाली फसलों की खेती करने पर ध्यान देना चाहिए। कीवी और फूल जैसी जल्दी खराब होने वाली बागवानी फसलों के निर्यात में रेल मंत्रालय सुपरफास्ट एसी डिब्बों के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकता है।

उन्होंने कृषि उत्पादों के विपणन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) के पुरूद्धार का सुझाव दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) और स्वयं सहायता समूह, आय बढ़ाने तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को सृजित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुलिस अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सहायता प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों को कानून व व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनाने के लिए वर्तमान के शांतिपूर्ण माहौल का उपयोग करना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य अनूठी विकास क्षमता से युक्त है। हमें उन विशिष्ट विकास क्षेत्रों की पहचान करने तथा इससे संबंधित कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसका कार्यान्वन समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। प्रणाली पारदर्शी और उत्तरदायी होनी चाहिए। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस लक्ष्य के प्रति कार्य करने का आग्रह किया।

इंडसइंड बैंक का क्यू1 शुद्ध लाभ 24 फीसदी बढ़कर 103535.72 करोड़ रुपये हो गया

मुंबई, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज 30 जून, 2018 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम को मंजूरी दे दी।

प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ श्री रोमेश सोबती ने कहा, ष्नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, बैंक ने अपनी विकास गति जारी रखी और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया. बैंक आगे बढ़ना जारी रखे हुए है और बैंकिंग परिचालन के दूसरे वर्ष में आगे बढ़ने के लिए विकास योजनाओं को सूचीबद्ध कर चुका है. डिजिटाइजेशन और ग्राहक सुविधा बैंक की रणनीति बनी हुई है जो ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं के माध्यम से मूल्य का निर्माण करेगी.

बैंक ने शुद्ध लाभ 24 फीसदी तक बढ़ाया और चालू तिमाही के लिए रिटर्न ऑन असेट पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 1.86 फीसदी के मुकाबले 1.91 फीसदी हो गई.(1)

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
(भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की यूनिट)
निर्माण एवं अनुरक्षण समूह
नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, **फोन नं.** (079) 26314092/26314097, **फैक्स नं.** (079) 26314904

निविदाएं आमंत्रित करने के लिए संक्षिप्त नोटिस

पी.आर.एल. के निदेशक की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए वस्तु दर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है :

क्र.	कार्य का शीर्षक	लगभग अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	कार्य पूरा करनेकी अवधि	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अवधि	बोली स्पष्टीकरण	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख और समय	निविदाएं खोलने की नियत तारीख और समय	ईएमडी
1.	एन आई टी सं.: **PRL/CMG/E-tender-02/2018-19 दिनांक 11-07-2018.** पी.आर.एल. मुख्य परिसर, अहमदाबाद में मरम्मत, नवीकरण और सुधार जैसे विविध अत्यावश्यक सिविल रखरखाव कार्य।	₹ 48.58	45 दिन	13.07.2018 को 10:00 बजे से 23.07.2018 को 14:30 बजे तक	13.07.2018 को 11:00 बजे से 24.07.2018 को 14:30 बजे तक	25.07.2018 14:30 बजे तक	26.07.2018 को 15:00 बजे तक	₹ 97,160/-

(1) निर्धारित अवधि के दौरान टेंडरविजार्ड के पास पंजीकरण करके एवं **निविदा प्रोसेसिंग शुल्क** का भुगतान करके ई-निविदा वेबसाईट **www.tenderwizard.com/ISRO** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है । इस वेबसाईट पर विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया दर्शाई गई है । निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ई-गेटवे के माध्यम से मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को देना होगा । **(2)** पात्रता मानदंड और अन्य विवरण के लिए, इच्छुक निविदाकर्ता www.isro.gov.in या www.prl.res.in वेबसाईट पर **विस्तृत निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी)** और **www.tenderwizard.com/ISRO** पर टेंडर फ्री व्यू का अवलोकन करें । कोई भी कठिनाई होने पर निविदाकर्ता श्री सुनील पटेल (मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के प्रतिनिधि) से मो. नंबर 9714881992 पर संपर्क कर सकते है ।

समूह प्रधान,सीएमजी, पी.आर.एल.